

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

बनाम

मैसर्स लक्ष्मी बिजनेस एंड सीमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य.

सिविल अपील संख्या 2909 वर्ष 2014

फरवरी 28, 2014

[के.एस.राधाकृष्णन एवं ए.के. सिकरी न्यायमूर्ति]

टैरिफ निर्धारण की शक्ति-आयोजित: विशेष रूप से एसईआरसी और राज्य विद्युत बोर्ड को हस्तांतरित इस शक्ति से पूरी तरह से वंचित है-विद्युत अधिनियम, 2003 के आने से पहले, विद्युत अधिनियम, 1910 और उसके बाद विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 लागू थे-यह संबंधित राज्यों में विद्युत बोर्ड था जो उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कर रहा था और संचालन दरों का निर्धारण कर रहा था जिस पर बिजली की आपूर्ति की जानी थी-विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, एसईआरसी-2003 अधिनियम को टैरिफ फ्रेम करने की शक्ति दी गई है, जिसने टैरिफ विनियमन सहित सभी प्रकार के विनियमों से सरकार को दूर कर दिया है, जो अब विशेष रूप से एसईआरसी को सौंपा गया है-इस प्रकार, राज्य विद्युत बोर्डों के पास टैरिफ फ्रेम करने की कोई शक्ति नहीं है जो एसईआरसी-विद्युत अधिनियम, 2003-विद्युत अधिनियम, 1910-विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनन्य डोमेन के तहत है।

एस. ई. आर. सी. द्वारा टैरिफ का निर्धारण-एच. टी. उपभोक्ताओं से मांग शुल्क जारी करना-आयोजित: 1994 एच. टी. समझौते को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत नहीं रखा गया था और टैरिफ संरचना-एच. टी. उपभोक्ताओं से मांग शुल्क जारी करने पर विचार किया गया था और दिनांक 27 के टैरिफ आदेश में इसे प्रभावी बनाया गया था। 12. 2003 जो 1.1.2004 को प्रभावी हुआ।

देरी/बाधाएं: रिट याचिकाएं दायर करने में देरी-1994 एचटी समझौते के खंड 4 (सी) के आधार पर जेएसईबी द्वारा उठाए गए बिल, 2004 की टैरिफ अनुसूची के निर्माण के बाद भी। - डिस्कनेक्ट के खतरे के तहत किया गया भुगतान - लिखित याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पहले की

अवधि के लिए उठाए गए बिलों के तहत ली गई अतिरिक्त राशि को वापस करने का निर्देश - इस आधार पर चुनौती दी गई कि उपभोक्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर करने में देरी हुई थी - आयोजित: देरी को विधिवत समझाया गया था उपभोक्ताओं ने डिस्कनेक्शन के खतरे के कारण जेएसईबी द्वारा उठाए गए बिलों की राशि का भुगतान किया था - ऐसा करते समय, उन्होंने जे. एस. ई. बी. के साथ विशिष्ट याचिका दायर की थी कि अब उसे 2004 की टैरिफ अनुसूची के अनुसार बिलों को उठाना था - यह मामला जे. एस. ई. बी. के स्तर पर विचाराधीन रहा जो 2004 की टैरिफ अनुसूची के स्पष्टीकरण के लिए अदालत के साथ-साथ एस. ई. आर. सी. का दरवाजा खटखटाता रहा।

वर्ष 1994 में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (जे. एस. ई. बी. के हित में पूर्ववर्ती) और उपभोक्ताओं के बीच एच. टी. समझौता किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बिजली की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं से जे. एस. ई. बी. द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को निर्धारित किया गया था। समझौते के खंड 4 (सी) में न्यूनतम गारंटी शुल्क का प्रावधान था। वर्ष 2003 में विद्युत अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत शुल्क तय करने की शक्ति एस. ई. आर. सी. को दी गई थी। एस. ई. आर. सी. ने विद्युत अधिनियम की धारा 86 के तहत नई टैरिफ अनुसूची (2004 टैरिफ अनुसूची) तैयार करने का आदेश पारित किया। उपभोक्ता प्रत्यर्थी की शिकायत यह थी कि जे. एस. ई. बी. ने समझौते में निर्दिष्ट खंड 4 (सी) के अनुसार बिल भेजना जारी रखा, जिसका विरोध में उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया गया था। मई 2010 में, उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों को इस आधार पर रद्द करने के लिए रिट याचिकाएं दायर की गईं कि इसे समझौते के खंड 4 (सी) के अनुसार गलत तरीके से उठाया गया था, जिसका एसईआरसी द्वारा 2004 की टैरिफ अनुसूची के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। हालाँकि, जे. एस. ई. बी. ने तर्क दिया कि उपभोक्ताओं के साथ किया गया एच. टी. समझौता अभी भी बना हुआ है क्योंकि 2004 की टैरिफ अनुसूची ने इस समझौते को बचा लिया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।

तत्काल अपीलों में जो प्रश्न विचार के लिए उठे थे वे थे: क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात्, जो 10.6.2003 को प्रवृत्त हुआ था और 2003 के अधिनियम के अनुसार झारखंड राज्य विद्युत

विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा दिनांक 27. 12.2003 को नया प्रशुल्क आदेश पारित किए जाने के पश्चात्, राज्य विद्युत बोर्ड अभी भी अपने द्वारा निर्धारित प्रशुल्क वसूल सकता है; क्या एचटीएस-1 श्रेणी के उपभोक्ता के लिए मांग प्रभार के मुद्दे को एसईआरसी प्रशुल्क आदेश दिनांक 27.12.2003 द्वारा गैर-विचारित छोड़ दिया गया है ताकि इसे राज्य में विद्यमान रीति से जारी रखा जा सके या क्या इसे 27. 12.2003 के प्रशुल्क आदेश में, जो 1.100.24 से प्रभावी हुआ है, विचार किया गया है और उस पर प्रभाव डाला गया है; धारा 185 का क्या प्रभाव होगा (एचटीएस-1 श्रेणी के उपभोक्ता के लिए प्रशुल्क प्रभार के मुद्दे को एसईआरसी प्रशुल्क आदेश दिनांक 27.12.2003 द्वारा गैर-विचारित छोड़ दिया गया है)

अपीलों की खारिज करते हुए न्यायालय ने माना: 1. री. : विद्युत अधिनियम 2003 के तहत एसईआरसी की शक्ति। विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने से पहले, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और उसके बाद विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 पारित किया गया था। यह संबंधित राज्यों में विद्युत बोर्ड था जो उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कर रहा था और संचालन दरों को निर्धारित कर रहा था जिस पर बिजली की आपूर्ति की जानी थी। अधिनियम, 1948 की धारा 49 ने बोर्ड को ऐसे नियमों और शर्तों पर किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति करने का अधिकार दिया जो बोर्ड उचित समझता है और समय-समय पर ऐसी आपूर्ति के उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है और ऐसी आपूर्ति के उद्देश्य के लिए समान टैरिफ तैयार करने का अधिकार दिया गया था। अधिनियम 1948 की धारा 49 (1) के तहत शुल्क तय करने की इस शक्ति में न्यूनतम गारंटी शुल्क तय करने की शक्ति शामिल थी। बिहार राज्य में, इस तरह की दरें 1993 के टैरिफ में तय की गई थीं। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एचटी उपभोक्ताओं के लिए शुल्क का प्रावधान किया गया था।

वहाँ एचटी उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। एचटीएस-I, II और III। तत्काल अपील में दोनों उपभोक्ताओं को एचटी-I श्रेणी में रखा गया था। एचटी समझौता दिनांक 26.4.1994 को बोर्ड और उपभोक्ताओं के बीच किया गया था। इस समझौते के खंड 4 के अनुसार, उपभोक्ताओं को बोर्ड द्वारा तैयार किए गए टैरिफ के अनुसार और समय-

समय पर उपभोक्ताओं को लागू उचित दरों पर इस तरह से आपूर्ति की गई और पंजीकृत या आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए बोर्ड को भुगतान करना था। यह आपूर्ति श्रेणी की उस श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम अनुबंध मांग के अधीन था जिसमें उपभोक्ताओं ने महसूस किया। खंड 4 (बी) ने समझाया कि प्रत्येक महीने के लिए उपभोक्ता की अधिकतम मांग किलोवोल्ट एम्पीयर (केवीए) की सबसे बड़ी कुल राशि होगी जो महीनों में किसी भी लगातार 30 मिनट के दौरान आपूर्ति के बिंदु पर उपभोक्ताओं को वितरित की गई थी। खंड 4 (सी) के अनुसार जे एस इ बी अनुबंध मांग के 75% के आधार पर ऊर्जा बिल बढ़ा रहा था।

[पैरा 6] [463-एफ-एच; 464-ए-जी]

1.2. विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमित होने के बाद, एस. ई. आर. सी. को शुल्क तय करने का अधिकार दिया गया था। यह शक्ति अधिनियम के तहत एस. ई. आर. सी. को वैधानिक रूप से प्रदान की गई थी। इस अधिनियम के पारित होने से पहले, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत, झारखंड एसईआरसी का गठन झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। इसके कार्यों और कर्तव्यों को सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम की धारा 22 के अनुसार अधिसूचित किया गया था। विद्युत अधिनियम, 20.03, विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को पारित किए जाने पर निरस्त कर दिया गया। साथ ही, अधिनियम 2003 ने 1998 अधिनियम के तहत गठित एस. ई. आर. सी. को मान्यता दी। 2004 एस. ई. आर. सी. द्वारा बनाई गई टैरिफ अनुसूची अधिनियम की धारा 86 (ए) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही थी। अधिनियम, 2003 बिजली से संबंधित सभी मामलों पर एक विस्तृत संहिता है जो उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए अलग-अलग उपयोगिताओं में राज्य बिजली बोर्डों को "अलग" करने का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा, विनियामक व्यवस्था एस. ई. आर. सी. को सौंपी गई है जिसे व्यापक जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस अधिनियम ने सरकार को टैरिफ विनियमन सहित सभी प्रकार के विनियमों से दूर कर दिया है, जो अब विशेष रूप से एस. ई. आर. सी. को सौंपा गया है। इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि राज्य विद्युत बोर्डों के पास शुल्क निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है जो एस. ई. आर. सी. के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कानूनी स्थिति को

न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है।

[पैरा 7 से 10] [464-जी-एच; 465-ए-सी। और एफ; 467-डी]

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2010) 4 एससीसी 603:2010 '(3) एससीआर 609; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड। (2008) 4 एससीसी 755:2008 (4) एससीआर 822; एपी। ट्रांस्को बनाम साई रिन्यूएबल पावर (पी) लिमिटेड (2011) 11 एस. सी. सी. 34:2010(8) एस. सी. आर. 636-पर निर्भर।

2. क्या दिनांक 26.4.1994 का करार 2004 की टैरिफ अनुसूची में सहेजा गया है?

2.1. जे. एस. ई. बी. के अनुरोध पर ही एस. ई. आर. सी. ने टैरिफ शुल्क तय किया जब उसने इस उद्देश्य के लिए एस. ई. आर. सी. से संपर्क किया। एसईआरसी के समक्ष जेएसईबी द्वारा दायर टैरिफ याचिका में, जेएसईबी ने अनुबंध मांग के 75% के तरीके को जारी रखने का प्रस्ताव नहीं किया और एसईआरसी ने मांग शुल्क 140-केवी-महीने की अनुमति दी। टैरिफ आदेश में अनुलग्नक 5.1 है जिसमें 'टैरिफ अनुसूची' है। यह टैरिफ अनुसूची जो टैरिफ प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है, राज्य पर भी बाध्यकारी है। हालांकि, जे. एस. ई. बी. ने स्वयं एस. ई. आर. सी. के लिए अपने आवेदन/संदर्भ में कोई न्यूनतम गारंटी शुल्क तय करने के लिए नहीं कहा था। जे. एस. ई. बी. ने जी. एस. ई. आर. सी. के समक्ष प्रस्तुत 2003-04 के लिए प्रशुल्क निर्धारण के अपने प्रस्ताव में एच. टी. एस. (उच्च तनाव सेवा) उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों सहित सभी उपभोक्ताओं के संबंध में मौजूदा प्रशुल्क और उसके द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क दोनों का संकेत दिया। एस. ई. आर. सी. ने आवश्यक कवायद करने के बाद सभी श्रेणियों के शुल्क तय किए। एचटीएस-I उपभोक्ताओं के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तावित टैरिफ को मौजूदा टैरिफ के साथ 2004 की टैरिफ अनुसूची की तालिका 5.28 और 5.29 में पुनः प्रस्तुत किया गया था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एसईआरसी द्वारा न्यूनतम गारंटी शुल्क के पहलू पर विधिवत विचार किया गया था।

[पैरा 12,13] [469-सी-एफ; 470-जी-एच; 471-ए]

2.2. टैरिफ आदेश से यह भी पता चला कि एसईआरसी ने जेएसईबी के प्रस्ताव की तुलना भारत में अन्य राज्यों में प्रचलित टैरिफ से भी की थी और इसके विस्तृत विश्लेषण के बाद, इसने एचटीएस उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को मंजूरी दी, जिसका उल्लेख 2004 की टैरिफ अनुसूची की तालिका 5.31 में किया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एस. ई. आर. सी. न्यूनतम गारंटी शुल्क से संबंधित खंड से अनजान था जो जे. एस. ई. बी. अपने उपभोक्ताओं से उनके साथ किए गए पहले के समझौतों के अनुसार ले रहा था। 2004 की टैरिफ अनुसूची में चर्चा से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जिसमें एससीआरसी ने एचटीएस उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को संशोधित करने और मंजूरी देने के लिए विशिष्ट कारण दिए थे। उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि एस. ई. आर. सी. ने विद्युत बोर्ड के मांग शुल्क के उनके दावे और उससे प्रभारित किए जाने के तरीके के संबंध में उनके प्रस्ताव पर विचार किया है। बोर्ड खंड 5.1 की सहायता नहीं ले सकता है, जिसमें यह पाया गया था कि कुछ मामलों पर विचार नहीं किया गया है और वे वैसे ही बने रहेंगे जैसे वे राज्य में अस्तित्व में थे क्योंकि विद्युत बोर्ड द्वारा मांग प्रभार के लिए एक विशिष्ट प्रस्ताव किया गया है और साथ ही जिस तरीके से इसे प्रभारित किया जाएगा और इस प्रस्ताव पर एसईआरसी द्वारा विचार किया गया था और उसके बाद टैरिफ आदेश जारी किया गया है। जेएसईबी ने एसईआरसी के समक्ष स्पष्टीकरण आवेदन भी दायर किए थे जिसमें कहा गया था कि एचटी-1 उपभोक्ताओं के साथ समझौते के खंड 4 (सी) को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम मांग शुल्क समझौते के खंड 4 (सी) के तहत निर्धारित किया जाएगा। एस. ई. आर. सी. द्वारा इन आवेदनों को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। जे. एस. ई. बी. द्वारा उन आदेशों को चुनौती देने वाली कोई अपील नहीं की गई थी। इसलिए, जे. एस. ई. बी. के लिए अब यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि न्यूनतम गारंटी शुल्क के इस पहलू पर एस. ई. आर. सी. द्वारा 2004 की टैरिफ अनुसूची में विचार नहीं किया गया है।

[पैरा 14 से 16] [473-सी -डी ; 475-जी -एच ; 476-ए -इ]

3. री. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 का प्रभाव।

इस अवधि के दौरान लागू टैरिफ 2003-04 की अवधि के लिए दिनांक 27.12.2003 का टैरिफ आदेश था, जो विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन विधि द्वारा प्रवृत्त था। इस प्रकार, भले ही यह इस आधार पर माना जाता है कि पहले किए गए वैधानिक समझौतों को सुरक्षित रखा गया था, विचाराधीन समझौते को 2004 टैरिफ अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 185 पर आधारित तर्क भी इस मामले के परिणामों में कोई बदलाव नहीं लाएगा। उच्च न्यायालय के उस फैसले में कोई गलती नहीं थी जिसके खिलाफ अपील की गई थी। [पैरा 19,20] [479-एफ-जी; 481-ए-बी]

पंजाब राज्य बनाम मोहर सिंह 1955 (1) एससीआर 893; बीएसईएस बनाम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (2004) 1 एससीसी 195:2003 (4) स्प्लीमेंट। एससीआर 932-पर निर्भर |

4. यह प्रस्तुत किया गया था कि 1994 के समझौते के खंड 4 (ग) के आधार पर जेएसईबी द्वारा उठाए गए बिलों के रूप में रिट याचिकाएं दायर करने में देरी हुई थी, 2004 की टैरिफ अनुसूची के निर्माण के बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जा रहा था और उन्होंने केवल वर्ष 2010 में रिट याचिकाएं दायर करके अदालत का दरवाजा खटखटाया था और ऐसे परिदृश्य में, उच्च न्यायालय को कम से कम अपीलकर्ताओं को पहले की अवधि के लिए उठाए गए बिलों के तहत चार्ज की गई अतिरिक्त राशि को वापस करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था और यह उन उपभोक्ताओं के लिए अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा जिन्होंने बिजली के उपयोगकर्ता से राशि वसूल की होगी। जी में जहां तक रिट याचिका दायर करने में देरी का संबंध है, घटनाओं के कालक्रम से यह प्रतीत होता है कि इसे विधिवत समझाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपभोक्ताओं ने डिस्कनेक्शन के खतरे के कारण जेएसईबी द्वारा उठाए गए बिलों की राशि का भुगतान किया था ऐसा करते समय, उन्होंने जे. एस. ई. बी. के साथ विशिष्ट याचिका दायर की थी कि अब उसे 2004 की टैरिफ अनुसूची के अनुसार बिलों को उठाना था। यह मामला जे. एस. ई. बी. के स्तर पर विचाराधीन रहा जो 2004 की टैरिफ अनुसूची के स्पष्टीकरण के लिए अदालत के साथ-साथ एस. ई. आर. सी. का दरवाजा खटखटाता रहा। स्पष्टीकरण आवेदन दायर किए गए थे जिन्हें एस. ई. आर. सी. ने खारिज कर दिया था। हालाँकि, चूंकि इन आवेदनों को खारिज किए जाने के बाद भी जे. एस. ई. बी. ने अपने रुख से

निर्णय नहीं लिया, इसलिए उपभोक्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और रिट याचिकाएँ दायर कीं। इस प्रकार रिट याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का रुख करने के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। अन्यायपूर्ण और संवर्धन की याचिका अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। सबसे पहले, एकल न्यायाधीश या खंड पीठ के समक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई थी। विशेष अनुमति याचिका में, यह निवेदन पहली बार अपीलों की सुनवाई के समय किया गया था। इसके अलावा, यह कर के भुगतान का मामला नहीं है जो उपभोक्ताओं पर बोझ है।

[पैरा 21 से 23) (481-बी-एच; 482-ए-बी]

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग और अन्न. v. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (2013) 12 स्केल 397; मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (1997) 5 एससीसी 536-संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ

2010(3) एस. सी. आर. 609 पैरा 9 पर निर्भर
2008(4) एस. सी. आर. 822 पैरा 10 पर निर्भर
2010(8) एस. सी. आर. 636 पैरा 10 पर निर्भर
(2013) 12 स्केल 397 पैरा 17 को संदर्भित
1955(1)एस. सी. आर. 893 पैरा 17 पर निर्भर
2003(4) पूरक एस. सी. आर. 932 पैरा 19 पर निर्भर
(1997)5 एस सी सी 536 जो पैरा 23 को निर्दिष्ट है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2014 का 2909
साथ

सिविल अपील संख्या 2014 का 2910,2911 और 2913

अजीत कुमार सिन्हा, एम.एल. वर्मा, एम.एस. मित्तल, ए.के. गांगुली, ऐश्वर्या सिन्हा, अंभोज कुमार सिन्हा, हिमांशु शेखर, फैसल खान, एम.पी. झा, राम एकबल राँय, हर्षवर्धन झा, दिलीप पिल्लई, कौशिक पोद्दार, शंकर लाल

अग्रवाल, देवाशीष भरूका, जसमीत कुआर, चंदन कुमार राय, रवीन दुबे
उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था -

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी,

1. विलम्ब क्षमा किया गया।
2. अनुमति प्रदत्त की गई।
3. दोनों प्रकरणों में अपीलकर्ता झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) है, जो दो अपीलों में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 जुलाई 2011 के सामान्य निर्णय से व्यथित है। ये अपीलें अपीलकर्ता जेएसईबी द्वारा दो रिट याचिकाओं में उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 17 फरवरी 2010 के आदेशों के विरुद्ध दाखिल की गई थीं, जो मेसर्स लक्ष्मी बिजनेस एंड सीमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड और मेसर्स लक्ष्मी इस्पात उद्योग (प्रत्येक अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 के रूप में सूचीबद्ध और इसके बाद 'उपभोक्ता' के रूप में संदर्भित किया जायेगा) द्वारा दाखिल की गई थीं। इन प्रत्यर्थीगण ने उन रिट याचिकाओं में जेएसईबी द्वारा उठाए गए बिलों की वैधता पर प्रश्न उठाया था, मुख्य रूप से इस आधार पर कि बिल झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद 'एसईआरसी' के रूप में संदर्भित किया जायेगा) द्वारा निर्धारित टैरिफ के विपरीत और उससे अधिक थे। उनके तर्क को विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की डिवीजन बेंच

ने भी पुष्टि की है।

4. इसमें शामिल विवाद सारांश में इस प्रकार है कि , वर्ष 1994 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी के हित में पूर्ववर्ती) और उपभोक्ताओं के बीच एचटी समझौता किया गया था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जेएसईबी द्वारा इन उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए जेएसईबी द्वारा उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले टैरिफ को निर्धारित किया गया था। समझौते के खंड 4(सी) में न्यूनतम गारंटी शुल्क का प्रावधान था। वर्ष 2003 में विद्युत अधिनियम अधिनियमित गया। निस्संदेह, इस अधिनियम के तहत टैरिफ निर्धारण करने की शक्ति एसईआरसी को दी गई है। एसईआरसी ने विद्युत अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जायेगा) की धारा 86 के तहत नई टैरिफ अनुसूची (जिसे संक्षेप में '2004 टैरिफ अनुसूची' संदर्भित किया जायेगा) निर्धारण करने का आदेश पारित किया । हालाँकि, जेएसईबी ने समझौते में उल्लिखित खंड 4 (सी) के अनुसार बिल भेजना जारी रखा, जिसका उपभोक्ताओं ने विरोध के तहत भुगतान किया। मई 2010 में, उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बिलों को इस आधार पर रद्द करने के लिए रिट याचिकाएं दाखिल की गईं कि यह समझौते के खंड 4 (सी) के अनुसार गलत तरीके से बढ़ाया गया था, जिसका एसईआरसी द्वारा 2004 टैरिफ अनुसूची के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालाँकि, जेएसईबी ने तर्क दिया कि उपभोक्ताओं के साथ किया गया एचटी समझौता अभी भी प्रभावी है क्योंकि 2004 टैरिफ

अनुसूची इस समझौते का संचय करती है।

5. चूंकि उपभोक्ताओं की रिट याचिकाये स्वीकार की गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को डिवीजन बेंच ने पहले ही स्थिर रखा है, यह स्पष्ट है कि जेएसईबी द्वारा उठाई गई याचिकाओं को उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला है। हमारे सामने भी यही तर्क प्रस्तुत किये थे जो जेएसईबी ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये थे। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 185 (2) (ए) सहपठित साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 (बी) भी पहले के अधिनियम के पिछले संचालन की स्पष्ट रूप से संरक्षण करती है, जो उसके तहत विधिवत किया या संचय किया गया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इन अपीलों में विचारण के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे निम्नलिखित हैं:

- (i) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद, जो दिनांक 10.6.2003 को लागू हुआ और झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 27.12.2003 को नए टैरिफ आदेश पारित होने के बाद, अधिनियम 2003 के अनुसार क्या राज्य विद्युत बोर्ड अभी भी स्वयं द्वारा निर्धारित टैरिफ वसूल सकता है?
- (ii) क्या एचटीएस-1 श्रेणी के उपभोक्ताओं को मांग शुल्क का मुद्दा राज्य आयोग द्वारा दिनांक 27.12.2003 के टैरिफ आदेश में

गैर-विचारणीय छोड़ दिया गया है ताकि इसे राज्य में प्रचलित तरीके से जारी रखा जा सके या क्या टैरिफ आदेश दिनांक 27.12.2003 में इस पर विचार किया गया है और इसे प्रभावित किया गया है जो 1.1.2004 से प्रभावी हुआ है?

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 से पहले बोर्ड और उपभोक्ता पर किए गए एचटी आपूर्ति समझौते पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 (निरसन और व्यावृत्ति) का क्या प्रभाव होगा ?

6. इन प्रश्नों के निराकरण के दौरान, हम आगे के मौलिक तथ्यों और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की विस्तृत प्रस्तुतियों का वर्णन करेंगे।

1. पुनः विद्युत अधिनियम 2003 के तहत एसईआरसी की शक्ति।

अधिनियम 2003 में निहित विधिक स्थिति शायद ही विवाद में हो। वर्ष 2003 में इस अधिनियम के लागू होने से पहले, हमारे पास भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 था और इसके पश्चात विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 पारित किया गया था। यह संबंधित राज्यों में विद्युत बोर्ड हैं जो उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति कर रहा था और संचालन दरों का निर्धारण कर रहा था जिस पर विद्युत की आपूर्ति की जानी थी। अधिनियम, 1948 की धारा 49 ने बोर्ड को ऐसे नियमों और शर्तों पर किसी भी व्यक्ति को विद्युत की आपूर्ति करने का अधिकार दिया, जैसा कि बोर्ड उचित समझता है और समय-समय पर ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए बनाया

जाता है और उन्हें ऐसी आपूर्ति के उद्देश्य के लिए एक समान टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। अधिनियम 1948 की धारा 49(1) के तहत टैरिफ निर्धारित करने की इस शक्ति में न्यूनतम गारंटी शुल्क तय करने की शक्ति भी शामिल थी। बिहार राज्य में ऐसी दरें वर्ष 1993 के टैरिफ में निर्धारित की गई थीं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ एचटी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का प्रावधान किया गया है। वहां एचटी उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां का उल्लेख किया गया। जिसमें एचटीएस-I, II और III है। वर्तमान अपील में दोनों उपभोक्ताओं को एचटी-I श्रेणी में रखा गया था। बोर्ड और उपभोक्ताओं के बीच दिनांक 26.4.1974 को एचटी समझौता निष्पादित किया गया। इस समझौते के खंड 4 के अनुसार, उपभोक्ताओं को बोर्ड द्वारा निर्धारित और समय-समय पर लागू टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए लागू उचित दरों पर आपूर्ति की गई और पंजीकृत या ली गई विद्युत के लिए बोर्ड को भुगतान करना था। यह आपूर्ति श्रेणी की उस श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम अनुबंध मांग के अधीन था जिसमें उपभोक्ता आते थे। खंड 4(बी) में बताया गया है कि प्रत्येक माह के लिए उपभोक्ता की अधिकतम मांग किलोवोल्ट एम्पीयर (केवीए) की सबसे बड़ी कुल मात्रा होगी जो उपभोक्ताओं को महीनों में लगातार 30 मिनट के दौरान आपूर्ति के बिंदु पर वितरित की गई थी। चूंकि जेएसईबी ने खंड 4 (सी) के अनुसार शुल्क पर काम किया है, जिसकी वह मांग कर रहा है, हम यहां नीचे उक्त खंड को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं:

“4(सी) खंड 13 के प्रावधान के अधीन, किसी भी महीने में आपूर्ति के लिए अधिकतम मांग शुल्क महीने की अधिकतम केवीए मांग या अनुबंध मांग का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पर आधारित होगा। हालाँकि, पहले बारह महीनों की सेवा के लिए किसी भी महीने के लिए अधिकतम मांग शुल्क, उस महीने की वास्तविक मासिक अधिकतम मांग पर आधारित होगा।

इस प्रकार, उपरोक्त खंड के अनुसार, जेएसईबी अनुबंध मांग के 75% के आधार पर विद्युत बिल बढ़ोतरी कर रहा था।

7. जैसा कि ऊपर बताया गया है, विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित होने के बाद, टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति एसईआरसी को दी गई है। यह शक्ति अधिनियम के तहत एसईआरसी को वैधानिक रूप से प्रदान की गई है। हालाँकि, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इस अधिनियम के पारित होने से पहले, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1763 दिनांक 22 अगस्त 2002 के माध्यम से किया गया था। इसके कार्यों और कर्तव्यों को सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम की धारा 22 के अनुसार अधिसूचित किया गया था।
8. विद्युत अधिनियम, 2003 के पारित होने पर, विद्युत अधिनियम

1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, अधिनियम 2003, 1998 अधिनियम के तहत गठित एसईआरसी को मान्यता देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य खंड इस प्रकार है:

" विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग और साधारणतः विद्युत, उद्योग के विकास, उसमें प्रतिस्पर्धा को संवर्धन, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण: और सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति के, विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नियामक आयोगों का गठन और अपीलीय अधिकरण की स्थापना में सहायक उपाय करने, से सम्बंधित विधियों का समेकन करने और और उससे सम्बंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।"

9. यह भी विवादित नहीं है कि एसईआरसी द्वारा बनाई गई 2004 टैरिफ अनुसूची अधिनियम की धारा 86 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही है। न्याय दृशांत पीटीसी इंडिया लिमिटेड वी. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (2010) 4 एससीसी 603 में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम, 2003 विद्युत से संबंधित सभी विषयों पर एक विस्तृत संहिता है जो

उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को अलग-अलग उपयोगिताओं में "विभाजित" करने का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा, नियामक व्यवस्था राज्य विद्युत नियामक आयोगों को सौंपी गई है, जिन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस अधिनियम ने सरकार को टैरिफ विनियमन सहित सभी प्रकार के नियमों से दूर कर दिया है, जो अब विशेष रूप से एसईआरसी को सौंपा गया है। इस अधिनियम की योजना को रेखांकित करने वाली प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:

“2003 अधिनियम को विद्युत से संबंधित सभी विषयों पर एक विस्तृत संहिता के रूप में अधिनियमित किया गया है। यह उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए एसईबी को अलग-अलग उपयोगिताओं में विभाजित करने का प्रावधान करता है। यह विद्युत अधिनियम, 1910: विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को निरस्त करता है। विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 अधिनियम) के तहत परिकल्पित नीति के अग्रसण में, अधिनियम 2003 ने एक स्वतंत्र और पारदर्शी नियामक तंत्र की स्थापना को अनिवार्य किया है, और नियामक आयोगों को व्यापक जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। जबकि अधिनियम 1998 टैरिफ निर्धारण के क्षेत्र में स्वतंत्र विनियमन प्रदान करता है: 2003 अधिनियम ने सरकार को सभी प्रकार के विनियमन, अर्थात् लाइसेंसिंग, टैरिफ विनियमन, ग्रिड कोड

निर्दिष्ट करना, खुली पहुंच के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की सुविधा आदि से दूर कर दिया है। "[पैराग्राफ 17]

अधिनियम 2003 में आयोग द्वारा दोहरे कार्यों के निष्पादन के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। धारा 61 केंद्रीय आयोग द्वारा नियम बनाने के लिए सक्षम प्रावधान है: अधिनियम की धारा 61 के तहत टैरिफ के नियमों और शर्तों का निर्धारण नियामक आयोगों के डोमेन पर छोड़ दिया गया है , जबकि नियामक आयोगों द्वारा वास्तविक टैरिफ निर्धारण अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत आच्छादित है। वर्तमान मामले पर निर्णय लेने के लिए यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट करना एक कार्य है जो किसी उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत की आपूर्ति या विद्युत के पारेषण या विद्युत की व्हीलिंग या विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक टैरिफ निर्धारण से अलग और पृथक है।

26. 2003 के अधिनियम में "टैरिफ" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। "टैरिफ" शब्द की परिधि में न केवल दरों का निर्धारण बल्कि इससे संबंधित नियम और विनियम भी शामिल हैं। यदि कोई 2003 अधिनियम की धारा 61 को धारा 62 के साथ पढ़ता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक टैरिफ का

निर्धारण करेगा, इसमें वे नियम और शर्तें शामिल हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 61 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। 2003 अधिनियम के तहत, यदि कोई धारा 62 को धारा 64 के साथ पढ़ता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मूल्य निर्धारण की तरह टैरिफ निर्धारण की प्रकृति विधायी है, अधिनियम के तहत इसे धारा 111 के माध्यम से लागू किया गया है। ये प्रावधान, अर्थात् धारा 61, 62 और 64, नियामक आयोगों द्वारा निष्पादित कार्यों की दोहरी प्रकृति को दर्शाते हैं जैसे निर्णय लेना और टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट करना है।" [पैराग्राफ 25,26]
[जोर दिया गया]

10. इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि राज्य विद्युत बोर्डों के पास टैरिफ निर्धारण करने की कोई शक्ति नहीं है जो कि आयोग के विशेष डोमेन के अंतर्गत है। इस विधिक स्थिति को न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है। [गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड, (2008) 4 एससीसी 755 और ए. पी. ट्रांसको बनाम साई रिन्यूएबल पावर (पी) लिमिटेड (2011) 11 एससीसी 34 देखें।]
11. उपरोक्त विधिक स्थिति के बावजूद, जेएसईबी का तर्क है कि वर्ष 1994 में उपभोक्ताओं के साथ किया गया समझौता संचय रखा गया है और जेएसईबी को इसके खंड 4 (सी) के अनुसार टैरिफ वसूलने का अधिकार है। जेएसईबी के अनुसार यह स्थिति इस कारण से है कि

एसईआरसी द्वारा निर्धारित 2004 टैरिफ अनुसूची का खंड 1.4 ऐसी स्थिति प्रदान करता है और इसके अलावा अधिनियम 2003 की धारा 186 भी इस समझौते को संचय रखता है। इन दोनों पहलुओं पर, हम पहले ही उपरोक्त प्रश्न संख्या 2 और 3 विरचित चुके हैं और अब उनके निराकरण के लिए आगे बढ़ेंगे।

2. पुनः क्या दिनांक 26.4.1994 का समझौता 2004 टैरिफ अनुसूची द्वारा संचय किया गया है?

जेएसईबी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि 2004 टैरिफ अनुसूची में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो समझौते दिनांक 26.4.1994 में विशेष रूप से खंड 4 (सी) में निहित है और इसके अभाव में टैरिफ अनुसूची में 75% अनुबंध मांग के आधार पर बनाए गए विद्युत बिलों की संचय रखा था हुई। यह प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक 26.4.1994 का समझौता एक वैधानिक समझौता है क्योंकि यह 1948 के अधिनियम के तहत था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यह उपभोक्ताओं का मामला कभी नहीं था कि उपरोक्त प्रावधान को निरस्त, खंडित या अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसा भी नहीं हुआ है। इस उद्देश्य के लिए, श्री सिन्हा ने उपभोक्ताओं द्वारा दाखिल रिट याचिकाओं में दिए गए प्रकथनों पर भरोसा करने की कोशिश की और इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि उपभोक्ताओं ने भी स्वीकार किया कि अनुबंध की मांग का 75% का प्रावधान अनुपस्थित

हैं और 2004 में प्रदान नहीं किया गया था। उन्होंने एसईआरसी की 2004 टैरिफ अनुसूची के खंड 1.4 पर भी ठोस विश्वास जताया, जो इस प्रकार है:

"मीटर किराया, कम वोल्टेज पर आपूर्ति, कैपेसिटर चार्ज, विद्युत् शुल्क, छूट, सिक्योरिटी डिपाजिट, संविदा मांग से अधिक के लिए अधिभार आदि के संबंध में अन्य सभी नियम और शर्तें राज्य में मौजूदा के समान ही रहेंगी।"

इसके अलावा, टैरिफ आदेश 2003-04, खंड 5 में टैरिफ संरचना के डिजाइन और टैरिफ के विश्लेषण हैडिंग के तहत, विशेष रूप से खंड 5.4 में दो भाग टैरिफ संरचना और न्यूनतम गारंटी शुल्क से निपटा गया है, जिसमें कहा गया था कि "आदर्श रूप से, फिक्स्ड/डिमांड चार्ज सिस्टम पर व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा रखी गई मांग के अनुपात में लगाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उपभोक्ता की आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली को डिजाइन करने में उपयोगिता की सुविधा प्रदान करता है और इसलिए यह प्रणाली की निश्चित लागतों की वसूली के लिए एक उचित और उचित तंत्र है।"

श्री सिन्हा ने आगे तर्क दिया कि हाई टेंशन एग्रीमेंट दिनांक 26.8.2004 का खंड 4 (सी), जिस पर प्रत्यर्थी उपभोक्ता ने दिनांक 1.1.2004 के बहुत बाद बोर्ड के साथ हस्ताक्षर किए हैं, जब टैरिफ

आदेश 2003-04 प्रभावी हुआ, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि इसके बाद विद्युत आपूर्ति शुरू होने पर, प्रत्यर्थी पहले 12 महीनों में वास्तविक खपत के आधार पर केवीए/अधिकतम मांग शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके बाद अनुबंध मांग के 75% या दर्ज मांग के आधार पर, जो भी अधिक हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह समान रूप से स्थित सभी एचटीएस-1 उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होता है।

12. इस तर्क की विवेचन के क्रम में, हमें एसईआरसी द्वारा तैयार किए गए 2004 टैरिफ अनुसूची के प्रासंगिक प्रावधान को समझना होगा। यह अवलोकन करना उचित होगा कि एसईआरसी ने जेएसईबी के अनुरोध पर ही टैरिफ निर्धारित किया था जब उसने इस उद्देश्य के लिए एसईआरसी से संपर्क किया था। हमने पाया कि जेएसईबी द्वारा एसईआरसी के समक्ष दाखिल टैरिफ याचिका में, जेएसईबी ने अनुबंध की मांग के 75% के तरीके को जारी रखने का प्रस्ताव नहीं दिया और एसईआरसी ने 140-केवी-माह की मांग शुल्क की अनुमति दी। टैरिफ आदेश का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे विभिन्न धारा में विभाजित किया गया है, अर्थात्, धारा 1 'परिचय' वाला अध्याय है, धारा 2 'एआरआर' वाला अध्याय है यानी वार्षिक राजस्व आवश्यकता और बोर्ड द्वारा टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।, धारा 3 वह अध्याय है जिसमें हितधारकों से प्राप्त 'आपत्तियाँ' शामिल हैं, धारा 4 वह अध्याय है जिसमें 'एआरआर पर आयोग का विश्लेषण' है, धारा 5 वह अध्याय है जिसमें 'टैरिफ संरचना का

डिजाइन और टैरिफ का विश्लेषण' है, धारा 6 वह अध्याय है जिसमें अध्याय में 'जेएसईबी के लिए दिशा-निर्देश' हैं और अंत में संलग्नक 5.1 है जिसमें 'टैरिफ अनुसूची' है। यह टैरिफ अनुसूची, जो टैरिफ प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है, राज्य पर भी बाध्यकारी है। टैरिफ आदेश के संलग्नक 5.1 का प्रासंगिक भाग जिसमें राज्य आयोग ने हाई टेंशन सर्विस (एचटीएस) उपभोक्ताओं यानी प्रत्यर्थी संख्या 1 पर लागू श्रेणी पर टैरिफ प्रयोज्यता से निपटाया है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

श्रेणी: हाई टेंशन सर्विस (एचटीएस)

1. प्रयोज्यता

100 केवीए से अधिक अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं के लिए

2. सेवा का चरित्र

50 चक्र, 3 फेस 6.6 केवी/11 केवी/33 केवी या 132 केवी।

3. टैरिफ

एचटीएस के लिए टैरिफ

विवरण	टैरिफ*
रु./केवीए/माह	डिमांड चार्ज

एचटीएस	140
	ऊर्जा चार्ज
KWh/माह	रु./KWh
सम्पूर्ण खपत	4.00
	मासिक न्यूनतम चार्ज
आपूर्ति वास्ते 11 और 33 केवी	रु. 250/केवीए
आपूर्ति वास्ते 132 केवी	रु.400/केवीए

13. हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जेएसईबी ने स्वयं एसईआरसी को अपने आवेदन/संदर्भ में कोई न्यूनतम गारंटी शुल्क निर्धारण करने के लिए नहीं कहा था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जेएसईबी ने नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत 2003-04 के लिए टैरिफ निर्धारण के अपने प्रस्ताव में, एचटीएस (हाई टेंशन सर्विस) उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों सहित सभी उपभोक्ताओं के संबंध में मौजूदा टैरिफ और उसके द्वारा प्रस्तावित टैरिफ दोनों का संकेत दिया। एसईआरसी ने आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सभी श्रेणियों का टैरिफ निर्धारित कर दिया। मौजूदा टैरिफ के साथ एचटीएस-1 उपभोक्ताओं के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तावित टैरिफ को 2004 टैरिफ अनुसूची की तालिका 5.28 और 5.29 में पुनः प्रस्तुत किया गया है,

जो स्पष्ट रूप से परिलक्षित करेगा कि न्यूनतम गारंटी शुल्क के पहलू पर एसईआरसी द्वारा विधिवत विचार किया गया था। इसे प्रदर्शित करने के लिए, हम यहां नीचे दी गई दो तालिकाओं को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं:

5.28 एचटीएस-II उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ (मौजूदा/प्रस्तावित)

विवरण	टैरिफ
-------	-------

मांग शुल्क

	मौजूदा	प्रस्तावित
रु./केवीए/महीना	115	200

ऊर्जा शुल्क

रु./केवीएच	मौजूदा	प्रस्तावित
	1.72	4.30

ईंधन अधिभार शुल्क

रु./केवीएच	2.44	
------------	------	--

वार्षिक न्यूनतम गारंटी (एएमजी) शुल्क | |

<p>इस श्रेणी के लिए न्यूनतम अनुबंध मांग के अधीन, उस महीने की वास्तविक अधिकतम मांग के आधार पर उचित टैरिफ के अनुसार मासिक न्यूनतम मांग शुल्क या अनुबंध मांग का 75% जो भी अधिक हो। ऊर्जा शुल्क 30% के लोड फैक्टर और पावर फैक्टर 0.85 के आधार पर अनुबंध मांग पर 1.72/किलोवाट की दर से देय है।</p>	<p>उचित टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता से निम्नलिखित एएमजी शुल्क वसूला जाएगा। ईएचटीएस श्रेणी के लिए लागू ऊर्जा शुल्क की दर पर देय अनुबंध मांग पर 30% के लोड फैक्टर और पावर फैक्टर 0.9 पर आधारित एएमजी शुल्क।</p>
---	--

5.29 ईएचटीएस उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ (मौजूदा/प्रस्तावित)

विवरण	टैरिफ
-------	-------

मांग शुल्क

	मौजूदा	प्रस्तावित
रु./केवीए/महीना	110	200

--	--	--

ऊर्जा शुल्क

रु./केवीएच	मौजूदा	प्रस्तावित
	4.13	4.15

ईंधन अधिभार

रु./केवीएच	2.44	
------------	------	--

वार्षिक न्यूनतम गारंटी (एएमजी) शुल्क | |

इस श्रेणी के लिए न्यूनतम अनुबंध मांग के अधीन, उस महीने की वास्तविक अधिकतम मांग के आधार पर उचित टैरिफ के अनुसार मासिक न्यूनतम मांग शुल्क या अनुबंध मांग का 75% जो भी अधिक हो	उचित टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता से निम्नलिखित एएमजी शुल्क वसूला जाएगा। ईएचटीएस श्रेणी के लिए लागू ऊर्जा शुल्क की दर पर देय अनुबंध मांग पर 50% के लोड फैक्टर और पावर फैक्टर 0.9 पर आधारित एएमजी शुल्क।
ऊर्जा शुल्क 50% के लोड फैक्टर और पावर फैक्टर	

0.85 के आधार पर अनुबंध मांग पर 1.69/KWH की दर से देय है।	
--	--

14. टैरिफ आदेश से ज्ञात होता है कि एसईआरसी ने जेएसईबी के प्रस्ताव की तुलना भारत के अन्य राज्यों में प्रचलित टैरिफ से भी की थी और उसके विस्तृत विश्लेषण के बाद, उसने एचटीएस उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को मंजूरी दे दी, जिसका उल्लेख 2004 टैरिफ अनुसूची की तालिका 5.31 में किया गया है। अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि एसईआरसी न्यूनतम गारंटी शुल्क से संबंधित खंड से अनभिज्ञ था, जो जेएसईबी अपने उपभोक्ताओं से उनके साथ किए गए पहले के समझौतों के अनुसार वसूल रहा था। 2004 टैरिफ अनुसूची में निम्नलिखित चर्चा से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जिसमें एससीआरसी ने एचटीएस उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को संशोधित और अनुमोदित करने के लिए विशिष्ट कारण दिए हैं।

एसईआरसी ने इन अपीलों पर अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें इस संबंध में प्रावधान को नीचे दिए गए तरीके से समझाया गया है: “उपरोक्त तालिका से यह विदित है कि न्यूनतम शुल्क के प्रति कोई आम दृष्टिकोण नहीं है। हालाँकि, अगर हम उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश (132 केवीए से कम आपूर्ति) जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना करते हैं, तो कोई

न्यूनतम शुल्क नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आयोग आदर्श रूप से इस शुल्क को समाप्त करना चाहेगा, लेकिन वर्तमान वर्ष के लिए इस शुल्क के वास्तविक प्रभाव का पता लगाने के लिए जानकारी और डेटा की कमी के कारण उसने इस शुल्क को बरकरार रखा है। आयोग ने पहले ही बोर्ड को अगली याचिका में इस संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

वर्तमान वर्ष के लिए, आयोग न्यूनतम शुल्क के कारण उद्योगों पर भार नहीं बढ़ाना चाहेगा और अतः इसे मौजूदा स्तर पर रखने का प्रयास किया गया है। आयोग ने आपूर्ति का न्यूनतम स्तर और खपत का न्यूनतम स्तर माना है। इसके लिए आयोग ने एक दिन में दो (2) घंटे की औसत खपत को ध्यान में रखते हुए एचटीएस-I और एचटीएस-II श्रेणियों के लिए 10% लोड फैक्टर पर विचार किया है। ईएचटीएस और एचटी के लिए एक दिन में क्रमशः चार (4) घंटे और सात (7) घंटे की औसत खपत पर विचार करके क्रमशः 20% और 30% का विशेष लोड फैक्टर पर विचार किया है है। आयोग ने परिशीलन किया है कि यदि इन श्रेणियों के उद्योग इस न्यूनतम लोड फैक्टर को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें अपने अनुबंधित लोड को कम करना चाहिए। आयोग स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहता है कि यदि खपत उल्लिखित लोड फैक्टर से अधिक है, तो कोई न्यूनतम शुल्क लागू नहीं होगा।

खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, आयोग ने सभी उद्योगों के उपभोक्ताओं के लिए लोड फैक्टर छूट भी शुरू की है। इस परिभाषित लोड फैक्टर से अधिक की संपूर्ण खपत के लिए, ऐसी अतिरिक्त खपत के लिए ऊर्जा शुल्क पर छूट प्रदान की जाती है। आयोग चालू वर्ष के दौरान आपूर्ति की लागत के अनुरूप टैरिफ संरचना को संरेखित करना चाहता था, लेकिन भारी टैरिफ शॉक के कारण यह बाधित हो गया था, जिसका असर अन्य उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप अन्य श्रेणियों के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार एक सिद्धांत के रूप में आयोग ने टैरिफ संरचना में इस विकृति को कम करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। आयोग इस तथ्य से अवगत है कि झारखंड में एचटी उद्योग ने अतीत में क्रॉस सब्सिडी का खामियाजा उठाया है और उन पर लागू टैरिफ आपूर्ति की लागत से ऊपर है। हालाँकि, इस कदम के महत्व को मात्रात्मक गिरावट से नहीं बल्कि उस संकेत और इरादे से आंका जाना चाहिए जिसके तहत आयोग भविष्य में टैरिफ को और तर्कसंगत बनाने का इरादा रखता है।

15. हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि हम उन पैराग्राफों में की गई अवलोकन से सहमत हैं:

"...10. हम केवल मांग शुल्क के बारे में चिंतित हैं,

बल्कि यह कहें कि मांग शुल्क के बारे में चिंतित नहीं हैं, लेकिन उपभोक्ता द्वारा मांग शुल्क वसूलने के विरुद्ध मांग बढ़ाने के उद्देश्य से मांग शुल्क की गणना किस तरीके से की जा सकती है" जैसा कि टैरिफ आदेश के पृष्ठ 141 पर उल्लिखित है, टैरिफ आदेश 2003-04 में रु.140/- की दर से अनुमति दी गई है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि 1993 के टैरिफ के साथ-साथ अनुबंध में खंड 15.2 में एक फॉर्मूला दिया गया था जिसके आधार पर बोर्ड वास्तविक खपत इकाइयों के आधार पर मांग शुल्क वसूल रहा था, लेकिन विद्युत की यूनिटों की खपत के बावजूद उक्त राशि वसूल रहा था। अब प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि वे केवल उनके द्वारा उपभोग की गई इकाइयों के अनुसार उत्तरदायी हैं, न कि सूत्र के अनुसार उत्तरदायी हैं। हमने तालिका 5.27 में निहित बोर्ड के प्रस्ताव से पाया कि विद्युत् बोर्ड ने जानबूझकर (या अनजाने में) अपना प्रस्ताव केवल इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजूदा वार्षिक मांग शुल्क रु. 125/- प्रति केवीए प्रति माह है। बोर्ड के इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और अंततः 2003-04 के टैरिफ आदेश द्वारा मांग शुल्क की अनुमति दी गई, जिसका उल्लेख पृष्ठ 141 पर किया गया है, जिसके द्वारा केवल यह अनुमोदित किया गया है कि विद्युत बोर्ड 140/- प्रति केवीए प्रति माह चार्ज करने का हकदार होगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था, 2003-04 के टैरिफ आदेश ने इसे बढ़ाकर केवल 140/-

रुपये कर दिया।

11. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम यह नहीं मान सकते कि विद्युत नियामक आयोग ने मांग शुल्क के उनके दावे और इस शुल्क को लगाने के तरीके के संबंध में विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है..."

12. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता-बोर्ड खंड 5.1 की सहायता नहीं ले सकता है. जिसमें विद्युत नियामक आयोग ने यह परिशीलन किया है कि कुछ मामलों का निपटारा नहीं किया गया है और वे वैसे ही बने रहेंगे जैसे वे राज्य में अस्तित्व में थे क्योंकि विद्युत बोर्ड ने मांग शुल्क के साथ-साथ तरीके को लेकर भी एक खास प्रस्ताव रखा है, जिसमें इसका शुल्क लिया जाएगा और इस प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग ने विचार किया और उसके बाद टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया गया है..."

16. मामले को विवाद से परे रखने के लिए, हम एक और तथ्य को उजागर करना चाहेंगे, अर्थात् जेएसईबी ने एसईआरसी के समक्ष स्पष्टीकरण आवेदन पत्र भी दाखिल किया था , जिसमें यह तर्क दिया गया कि एचटी-आई उपभोक्ताओं के साथ समझौते के खंड 4(सी) को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम मांग शुल्क समझौते के खंड 4(सी) के तहत निर्धारित होंगे। इन आवेदनों को आयोग द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था। उन आदेशों को चुनौती देने वाली जेएसईबी द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अतः,

अब जेएसईबी के लिए यह तर्क देने में बहुत विलम्ब हो चुका है कि न्यूनतम गारंटी शुल्क के इस पहलू को एसईआरसी द्वारा 2004 टैरिफ अनुसूची में नहीं निपटाया गया है।

3. पुनः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 का आशय।

विद्युत अधिनियम की धारा 185 (2) (ए) और साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 (बी) पर आधारित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्हा की प्रस्तुति यह थी कि उपरोक्त प्रावधान के आधार पर पूर्व समझौता 1994, विद्युत बोर्ड और उपभोक्ताओं के बीच दर्ज इसकी खंड 4(सी) सहित संचय किया गया। अधिनियम की धारा 185(2)(ए) इस प्रकार है:

" निरसित विधियों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत बनाया गया कोई नियम या जारी की गई कोई अधिसूचना या किया गया निरीक्षण, आदेश या निकाली गई सूचना या की गई कोई नियुक्ति, पुष्टि या घोषणा या मंजूर की गई कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, प्राधिकार या छूट या निष्पादित किया गया कोई दस्तावेज या लिखत या दिया गया कोई निदेश, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा ;

हम यहां नीचे साधारण खंड अधिनियम की धारा 6(बी) को

भी पुनः प्रस्तुत करते हैं:

“इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियमित के पूर्व परवर्तन पर अथवा तदधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा: अथवा

17. यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि पिछले अधिनियम के संबंधित प्रावधान के तहत किए गए या लिए गए सभी कार्यों संचित हैं, प्रश्नगत समझौता जो वैधानिक शक्ति के प्रयोग में विद्युत बोर्ड द्वारा निष्पादित किया गया था और कानूनी बल था, उपरोक्त प्रावधानों के तहत संचित था। इस दलील को पेश करने के लिए, श्री सिन्हा ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (2013) 12 स्केल 397 के मामले में इस दलील के साथ इस न्यायालय के निर्णय का भी सन्दर्भ किया कि उपरोक्त निर्णय में इस पहलू को विशेष रूप से निपटाया गया था और अतः यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नहीं है। श्री सिन्हा ने बताया कि उस मामले में न्यायालयों ने विशेष रूप से अधिनियम, 2003 की धारा 185 में निहित निरस्त प्रावधान के प्रभाव को साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 (बी) के साथ पढ़ा और अभिनिर्धारित किया कि पिछले समझौतों को तब तक सहेजा गया था जब तक कि यह बताया जा सकता है कि उन्हें नष्ट करने का स्पष्ट इरादा था। उन्होंने स्टेट ऑफ़ पंजाब बनाम मोहर सिंह 1955 (1) एससीआर 893 के मामले में पिछले निर्णय के

निम्नलिखित अंश का सन्दर्भ किया, जिसे उपरोक्त निर्णय में उद्धृत किया गया है और इस प्रकार पढ़ा जाता है:

“जब भी किसी अधिनियम का निरसन किया जाता है, तो साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित परिणाम तब तक होंगे जब तक, जैसा कि धारा स्वयं कहती है, एक अलग इरादा प्रकट नहीं होता है। एक साधारण निरसन के मामले में विपरीत राय की अभिव्यक्ति के लिए शायद ही कोई जगह होती है। लेकिन जब निरसन के बाद उसी विषय पर नया कानून आता है तो हमें निस्संदेह नए अधिनियम के प्रावधानों का परिशीलन करना होगा, लेकिन केवल यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या वे एक अलग इरादे का संकेत देते हैं। जांच का विषय यह नहीं होगा कि नया अधिनियम स्पष्ट रूप से पुराने अधिकारों और देनदारियों को जीवित रखता है या नहीं, बल्कि क्या यह उन्हें नष्ट करने का इरादा प्रकट करता है। अतः हम इस व्यापक प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सकते कि साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 को तब खारिज कर दिया जाता है जब किसी अधिनियम को निरस्त करने के बाद नया कानून बनाया जाता है। धारा 6 ऐसे मामलों में भी लागू होगी जब तक कि नया कानून धारा के प्रावधानों के साथ असंगत या इसके विपरीत कोई इरादा प्रकट न करे। इस तरह की असंगति को नए कानून के सभी प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करके सुनिश्चित करना होगा और बचत खंड की अनुपस्थिति ही अपने

आप में महत्वपूर्ण नहीं है। इन सिद्धांतों के आलोक में हम अब वर्तमान मामले के तथ्यों के परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।"

(रेखांकित हमारा किया हुआ है)

उन्होंने उक्त निर्णय में निम्नलिखित चर्चा पर भी भरोसा किया :

“हमने उपरोक्त पैराग्राफों का उल्लेख किया है क्योंकि श्री गुप्ता ने तर्क दिया है कि जब किसी अधिनियम का निरसन किया जाता है और नए कानून का प्रतिस्थापन होता है, तो आमतौर पर एक मंच का निहित अधिकार नष्ट हो जाता है। 2003 अधिनियम की धारा 185 को संपूर्ण रूप से पढ़ने पर, इस प्रस्तुति को स्वीकार करना मुश्किल है कि भले ही साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 लागू होगी, फिर भी यह अपील के फोरम को नहीं सहेजता है। हमें ऐसा कोई विपरीत इरादा नहीं लगता कि साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 लागू नहीं होंगे। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार क्या अधिकार है और क्या नहीं है, के बीच का अंतर अक्सर बहुत उपयुक्त होता है। किसी कानून के निरस्त होने से जो अप्रभावित है, वह इसके तहत प्राप्त या अर्जित अधिकार है, न कि अधिकार प्राप्त करने की केवल आशा, या अपेक्षा, या

आवेदन करने की स्वतंत्रता है (एम एस शिवानंद बनाम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य MANU/एससी/0371/1979: (1980) 1 एससीसी 149) देखें।।"

18. इस तर्क की विवेचन के लिए, हमें उपभोक्ताओं के साथ किए गए 1994 के समझौते के कुछ प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन करना होगा। ये एचटी समझौते के पैरा 4(सी) और 11 हैं:

“4..(सी) किसी भी महीने में आपूर्ति के लिए अधिकतम मांग शुल्क अनुबंध मांग के 75% महीने के लिए अधिकतम केवीए मांग पर आधारित होगा, जो भी अधिक हो, खंड 13 के प्रावधान के अधीन.....

11. इस समझौते को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के प्रावधानों , उसके तहत बनाए गए नियमों, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के साथ-साथ नियमों, विनियमों (यदि कोई हो) टैरिफ और आपूर्ति के लिए नियम और शर्तों के अधीन पढ़ा और समझा जाएगा। विद्युत तैयार की गई और इसके तहत जारी की गई और फिलहाल लागू है जहां तक यह क्रमशः लागू हो सकता है और ऐसे सभी प्रावधान उनके और इस समझौते के नियमों और शर्तों के बीच किसी भी संघर्ष या असंगतता के मामले में प्रबल होंगे।

19. यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस अवधि के दौरान लागू टैरिफ 2003-04 की अवधि के लिए टैरिफ आदेश दिनांक 27.12.2003 था

जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विधि में प्रचलित था। इस प्रकार, उपरोक्त से क्या पता चलता है क्या यह कि भले ही हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि पहले किए गए वैधानिक समझौतों को सहेज लिया गया था, प्रश्नगत समझौते को 2004 टैरिफ अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस समय, हम **बीएसईएस बनाम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (2004) 1 एससीसी 195** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करना चाहेंगे, जिसमें निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियाँ की गईं।

"16. अधिनियम में "टैरिफ" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। "टैरिफ" वाणिज्य का एक कार्टेल है और आम तौर पर यह दरों की एक पुस्तक है। इसका मतलब टैरिफ में निर्दिष्ट ग्राहकों की श्रेणी या श्रेणियों को प्रदान की जाने वाली मानक कीमतों या शुल्कों की एक अनुसूची होगी। धारा 22 की उपधारा (1) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि राज्य आयोग विद्युत (थोक, बल्क, ग्रिड या खुदरा) और ट्रांसमिशन सुविधाओं के उपयोग के लिए भी टैरिफ निर्धारित करेगा। इसके पास वितरण उपयोगिताओं की विद्युत खरीद को विनियमित करने की शक्ति भी है, जिसमें वह मूल्य भी शामिल है जिस पर राज्य में ट्रांसमिशन, बिक्री, वितरण और आपूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन कंपनियों से खरीदी जाएगी। "उपयोगिता" को अधिनियम की धारा 2 (एल) में परिभाषित किया गया है और इसका मतलब है कि

कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ऊर्जा के उत्पादन, ट्रांसमिशन, बिक्री, वितरण या आपूर्ति में लगी हुई है, जैसा भी मामला हो। धारा 29 में यह प्रावधान है कि राज्य में विद्युत के अंतरराज्यीय पारेषण और विद्युत की आपूर्ति - थोक, बल्क या खुदरा - के लिए शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा और शुल्क राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। धारा 29 की उपधारा (2) से पता चलता है कि टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी और ऐसा करते समय आयोग खंड (ए) से (जी) में उल्लिखित कारकों द्वारा निर्देशित होगा। पहले संदर्भित विनियमन से पता चलता है कि उत्पादक कंपनियों और उपयोगिताओं को अपने टैरिफ के अनुमोदन के लिए पहले आयोग से संपर्क करना होगा, चाहे वह उत्पादन, पारेषण, वितरण या आपूर्ति के लिए हो और आपूर्ति के नियमों और शर्तों के लिए भी हो। वे अपने ग्राहकों से केवल वही टैरिफ वसूल सकते हैं जिसे आयोग ने मंजूरी दी हो। आयोग द्वारा अनुमोदित न किए गए टैरिफ को वसूलना एक अपराध है जो अधिनियम की धारा 45 के तहत दंडनीय है। अधिनियम और विनियमों के प्रावधान दर्शाते हैं कि आयोग के पास टैरिफ निर्धारित करने का विशेष अधिकार है। आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ अंतिम और बाध्यकारी है और लाइसेंसधारी, उपयोगिता या किसी अन्य के लिए अलग टैरिफ वसूलना अनुमेय नहीं है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 185 पर आधारित तर्क भी इस मामले के परिणामों में कोई बदलाव नहीं लाएगा। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के उस निर्णय में कोई गलती नहीं करते जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
21. इससे पहले कि हम अलग हों, अपीलकर्ता के एक और तर्क से निपटना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया था कि रिट याचिका दाखिल करने में विलम्ब हुआ था क्योंकि 1994 के समझौते के खंड 4 (सी) के आधार पर जेएसईबी द्वारा बिल जारी किए गए थे, यहां तक कि 2004 टैरिफ अनुसूची के निर्माण के बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जा रहा था और और उन्होंने वर्ष 2010 में रिट याचिका दाखिल करके न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस प्रकार, 5 वर्ष का विलम्ब और अतिविलंब हुआ। आगे तर्क दिया गया है कि ऐसे परिदृश्य में, उच्च न्यायालय को कम से कम अपीलकर्ताओं को पहले की अवधि के लिए उठाए गए बिलों के तहत ली गई अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था। अन्य संबंधित प्रस्तुति यह थी कि यह उन उपभोक्ताओं के लिए अन्यायपूर्ण समृद्धि होगा जो विद्युत के उपयोगकर्ता से राशि वसूल करेंगे।
22. जहां तक रिट याचिका दाखिल करने में विलम्ब का प्रश्न है, घटनाओं के कालक्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे विधिवत स्पष्ट

किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कनेक्शन काटने की धमकी के विरोध में उपभोक्ताओं ने जेएसईबी द्वारा बढ़ाए गए बिल की राशि का भुगतान किया था। ऐसा करते समय, उन्होंने जेएसईबी के समक्ष विशेष दलील रखी थी कि अब उसे 2004 टैरिफ अनुसूची के अनुसार बिल जारी करना चाहिए। यह मामला जेएसईबी के स्तर पर विचाराधीन रहा, जो 2004 टैरिफ अनुसूची के स्पष्टीकरण के लिए न्यायालय के साथ-साथ एसईआरसी से संपर्क करता रहा। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, स्पष्टीकरण आवेदन दाखिल किए गए थे जिन्हें आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, चूंकि जेएसईबी ने इन आवेदनों को खारिज करने के बाद भी अपने रुख पर कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए उपभोक्ताओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और रिट याचिकाएं दाखिल कीं। इस प्रकार रिट याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से संपर्क करने के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

23. अन्याय और समृद्धि की दलील अपीलकर्ताओं को उपलब्ध नहीं होगी। सर्वप्रथम , ऐसी कोई याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष या तो एकल न्यायाधीश या डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। विशेष अनुमति याचिका में, यह निवेदन वर्तमान अपीलों की सुनवाई के समय पहली बार किया गया था। इसके अलावा, यह कर के भुगतान का मामला नहीं है जो उपभोक्ताओं पर डाला गया भार है। यह केवल ऐसे मामलों में है जो **मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (1997) 5 एससीसी 536** में अभिनिर्धारित किए

गए थे, जिसमें अन्यायपूर्ण समृद्धि का प्रश्न विचार के लिए उठेगा। जहां तक वर्तमान जैसे मुद्दे का प्रश्न है, उपरोक्त निर्णय के पैरा 107 में ऐसा प्रश्न खुला छोड़ दिया गया था। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्यायपूर्ण समृद्धि की अवधारणा का कर्षों के अलावा रिफंड के लिए कोई उपयोग नहीं है, जैसा कि उसे पढ़ने से स्पष्ट है।

“107. एक स्पष्टीकरण: आबद्ध खपत के मामले में स्थिति को इस राय में हमारे द्वारा निपटाया नहीं गया है। हम उस प्रश्न को खुला छोड़ते हैं।

24. परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि अपीलों गुणरहित है और तदनुसार निरस्त की जाती है। कोई हर्जा खर्चा नहीं.

..... न्यायमूर्ति

(के.एस.राधाकृष्णन)

..... न्यायमूर्ति

(ए.के.सीकरी)

नई दिल्ली,

दिनांक 28 फ़रवरी 2014.

यह अनुवाद पीयूष आनन्द, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।